

भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1401
29.07.2025 को उत्तर के लिए नियत

“भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र”

1401. श्री देवसिंह चौहान:

श्री करण भूषण सिंह:

श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:

श्री खगेन मुर्मु :

श्री सुरेश कुमार कश्यप:

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2014 से वर्ष 2025 तक पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में पूंजीगत वस्तु उद्योग का हिस्सा कितने प्रतिशत है;

(ग) क्या सरकार ने ‘भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने संबंधी योजना’ के अंतर्गत किसी परियोजना को मंजूरी दी है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): वर्ष 2014 से वर्ष 2025 तक पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के उप-क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	पूंजीगत वस्तुओं का उप-क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25*
1	मशीन टूल्स-उत्पादन	4230	4726	5803	7294	9612	6152	6602	9307	11956	13571	14286
2	डाई, मोल्ड और प्रेस टूल्स	14647	15000	14750	16068	13600	13682	12294	13128	13915	15600	18400

3	वस्त्र मशीनरी	6960	6580	6650	6900	6865	5355	5093	11658	14033	14639	10461
4	मुद्रण मशीनरी-उत्पादन	15748	16916	13986	12968	12390	12678	10058	13215	16107	23479	29716
5	अर्थ मूविंग और माइनिंग मशीनरी	17000	18500	25000	31800	38900	31020	29021	28674	37551	73000	80750
6	प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनरी-उत्पादन	2950	2700	3000	3375	3100	2350	3710	3850	3912	4310	4827
7	खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी	20000	13206	15246	15600	8750	7547	10250	12210	13203	13863	15249
8	प्रसंस्करण संयंत्र उपकरण	18900	19000	19500	18400	27400	29250	21938	24000	23415	27396	31505
9	भारी विद्युत उपकरण	140308	147136	159257	176823	193781	179199	167706	219158	258832	302900	372200

* वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित आंकड़े

स्रोत: उद्योग संघ अर्थात् आईईईएमए, आईएमटीएमए, टीएजीएमए, एएफटीपीएआई, पीएमएमएआई, पीपीएमएआई, टीएमएमए, आईसीईएमए और आईपीएमएमए।

(ख): वर्तमान अनुमान के अनुसार, पूंजीगत वस्तु उद्योग देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 1.9% का योगदान देता है।

(ग) और (घ): भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने 25 जनवरी, 2022 को सामान्य प्रौद्योगिकी विकास और सेवा अवसंरचना को सहायता प्रदान करने के लिए "भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता संवर्धन की स्कीम- चरण-II" शुरू की। इसका कुल वित्तीय परिव्यय 1207 करोड़ रुपये है, जिसमें 975 करोड़ रुपये का बजटीय सहयोग और 232 करोड़ रुपये का उद्योग योगदान शामिल है। इस स्कीम के तहत कुल 33 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन 33 परियोजनाओं में 9 उत्कृष्टता केंद्र (सीआई), 5 साझा इंजीनियरिंग सुविधा केंद्र (सीईएफसी), 7 परीक्षण और प्रमाणन केंद्र, प्रौद्योगिकी विकास के लिए 9 उद्योग त्वरक और कौशल स्तर 6 तथा उससे ऊपर के लिए अर्हता पैक (क्यूपी) निर्माण की 3 परियोजनाएं शामिल हैं।
